राष्ट्र निर्माण में युवाओं की शक्ति सबसे बड़ी

नगालैंड में सीतारमण का संदेश—युवा ही भारत का भविष्य

नई दिल्ली, 16 नवबंर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नगालैंड में युवाओं को राष्ट्र निर्माण का मुख्य स्तंभ बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति निर्णायक भूमिका निभाएगी.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2047 के 'विकसित भारत' की नींव आज के ही युवा रखेंगे. अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान सीतारमण ने दीमापुर स्थित नगालैंड टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में एआई एवं फ्यूचर स्किल्स एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व के युवाओं को आधुनिक तकनीक में सक्षम बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है.

वित्त मंत्री ने अपने दौरे के दौरान वित्तीय समावेशन की दिशा में हो रहे प्रयासों की भी समीक्षा की. उन्होंने बताया कि प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर एक ऋण आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दूरस्थ इलाकों तक आसान ऋण सुविधा पहुँचाना है ताकि आर्थिक विकास में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. सीतारमण ने नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ बैठक में आकांक्षी जिलों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा की. उनके अनुसार, केंद्र सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर-पूर्व के युवा आने वाले दशक में भारत की तकनीकी और आर्थिक प्रगति का नेतृत्व करें.

उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर, एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कॉर्पोरेट साझेदारियों से नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं. नगालैंड के दीमापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अनिवार्य भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि देश अपने भविष्य को सुरक्षित तभी बना पाएगा, जब युवा एकजुट होकर नए कौशल, तकनीक और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

उन्होंने जोर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत का तकनीकी विकास युवा प्रतिभाओं के हाथों से ही आकार लेगा. अपने संबोधन में सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व विशेषकर नगालैंड को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2,05,185 करोड़ बढ़ा

मुंबई, 16 नवंबर. घरेलू शेयर बाजारों में रही तेजी के कारण बीएसई की शीर्ष 10 में शामिल आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) पिछले सप्ताह 2,05,185 करोड़ रुपये बढ़ गया, जबकि अन्य दो का 39,414 करोड़ रुपये घट गया. बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 55,653 करोड़ रुपये बढ़ गया. विविध क्षेत्रों में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमकैप में 54,941.84 करोड़ रुपये और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस के एमकैप में 40,758 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गयी. आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 20,834 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक का 10,523 करोड़ रु. बढ़ा.

डब्ल्यूटीओ सुधारों में भारत का नेतृत्व तय

वैश्विक व्यापार व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने की जरूरत

नई दिल्ली, 16 नवंबर. भारत ने एक बार फिर वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत करने का संकेत दिया है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि भारत विश्व व्यापार संगठन में आवश्यक सुधारों का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उनका कहना है कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने की जरूरत है, और यह तभी संभव है जब सुधारों की प्रक्रिया में विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की आवाज़ को प्रमुखता मिले. गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है जब महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ने भारत से संगठन में सुधारों का नेतृत्व करने का आग्रह किया है.

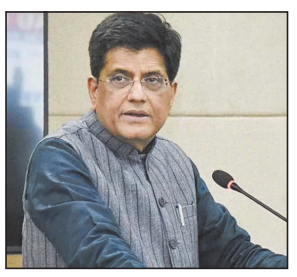

इसके जवाब में भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह सुधारों को आगे बढ़ाने में इच्छुक है, लेकिन यह प्रक्रिया संतुलित और वैश्विक कल्याण केंद्रित होनी चाहिए. भारत विश्व व्यापार संगठन में सुधारों की अगुवाई करने के लिए तैयार है. यह संकेत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विशाखापत्तनम में दिए, जहां वे सीआईआई के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए थे. गोयल ने कहा कि एफटीए सुधारों का उद्देश्य केवल कुछ विकसित देशों के हित पूरे करना नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली को समावेशिता की दिशा में ले जाना होना चाहिए.

> उन्होंने बताया कि सुधारों के लिए भारत विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के साथ व्यापक परामर्श करेगा. यह बयान महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को संगठन के सुधारों में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए. गोयल ने इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया आज भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, उसकी आर्थिक मजबूती को मान्यता दे रही है. अमेरिका समेत कई विकसित देश एफटीए में विवाद निपटान तंत्र, विशेष एवं भिन्न उपचार और वार्ता के ढांचे में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं.

चावल, गेहूं, दालों में साप्ताहिक तेजी

चीनी नरम, खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 16 नवंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव बढ़ गये. गेहूं और दालों के दाम भी चढ़ गये. चीनी सस्ती हुई जबकि खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया.

घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 76 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,818.29 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 11 रुपये की मजबूती के साथ 2,857.13 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. आटे की कीमत 3,312.86 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग अस्थिर रही. बीते सप्ताह मूंगफली तेल औसतन 149 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया. सरसों तेल की औसत कीमत स्थिर रही. पाम ऑयल में 21 रुपये प्रति क्विंटल की साप्ताहिक बढ़त देखी गयी.

यूएलआईपी के जरिए बदलेगा आंध्र का लॉजिस्टिक्स सिस्टम

नई दिल्ली, 16 नवबंर. भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के उपक्रम एनआईसीडीसी और एनएलडीएसएल के साथ एक बड़ा करार किया है. इस समझौते का उद्देश्य राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, तेज, सुलभ और डेटा-आधारित बनाना है. यह करार विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू स्वयं मौजूद रहे. इस समझौते के तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की मदद से एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा.

एफपीआई ने की 6,092 करोड़ की बिकवाली

मुंबई, 16 नवंबर. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने नवंबर में अबतक इक्विटी बाजार में 6,092 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नवंबर के पहले दो सप्ताह में इक्विटी बाजार में एफपीआई शुद्ध रूप से बिकवाल रहे. उन्होंने इक्विटी बाजार से शुद्ध रूप से 6,092 करोड़ रुपये की निकासी की. वहीं, डेट बाजार में उन्होंने 6,397 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया.

म्यूचुअल फंड में इस महीने अबतक एफपीआई का शुद्ध निवेश 350 करोड़ रुपये रहा है.

पहले दो सप्ताह में इक्विटी बाजार में एफपीआई शुद्ध रूप से बिकवाल रहे

डेट बाजार में उन्होंने 6,397 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया

हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने 79 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है. इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने भारतीय पूंजी बाजार में नवंबर में 575.87 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है.

इससे पहले अक्टूबर में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 35,246 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था जबकि जून से सितंबर के बीच लगातार चार महीने तक वे बिकवाल रहे थे. इस पूरे कैलेंडर वर्ष में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार में 48,789 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है.

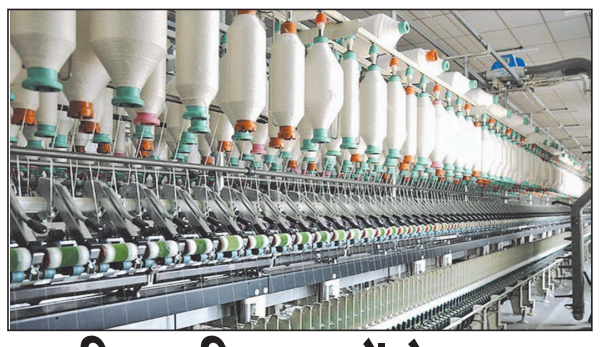

जीएसटी सुधारों के बाद कृत्रिम धागों से बढ़ेगा उद्योग

कपड़ा उद्योग को मिलेगी गति

नयी दिल्ली, 16 नवंबर. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत नयी पीढ़ी के सुधारों में कपास और कृत्रिम धागों (एमएमएफ) पर कर की दर एक समान पांच प्रतिशत कर दी गयी है जिससे कपड़ा उद्योग की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है.

कपड़ा उद्योग पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग का योगदान 2.3 प्रतिशत रहा. कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 13 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत है. भारत कपड़े और वस्त्रों का दुनिया में छठा सबसे बड़ा निर्यातक है. वित्त वर्ष 2023-24 में 34.4 अरब डॉलर का कपड़ा (तैयार वस्त्र और अन्य उत्पाद समेत) निर्यात किया गया था और इस क्षेत्र के वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी 3.91 प्रतिशत है. कृषि के बाद यह सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है. इसमें 4.5 करोड़ लोग सीधे काम करते हैं. कपास उगाने में पानी की काफी खपत के कारण यह अधिक महंगा होता है. यही कारण है कि दुनिया में अब कृत्रिम धागे ही ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं. जीएसटी के तहत सितंबर तक कपास पर पांच प्रतिशत और एमएमएफ पर 18 प्रतिशत कर लग रहा था. कारण देश में एमएमएफ का इस्तेमाल अब भी कपास से पीछे है. गत 22 सितंबर से लागू अगली पीढ़ी के सुधारों में अब कपास और एमएमएफ दोनों पर बराबर कर लगाया जा रहा है.

जीएसटी सुधारों से घरेलू बिक्री बढ़ेगी

डोढिया समूह के निदेशक भद्रेश डोढिया ने बताया कि जीएसटी सुधारों के बाद अब एमएमएफ को कॉटन से बेमेल प्रतिस्पर्धा नहीं करनी होगी. इससे कीमतें कम होंगी और निर्यात में भारती उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे तथा घरेलू बिक्री बढ़ेगी. कॉटन और कृत्रिम धागों की तुलना पर उन्होंने कहा, यह सही है कि कपास का स्पर्श, संवदेन और वह जिस तरह से शरीर तक हवा पहुंचने देता है, किसी और कपड़े के लिए उसकी जगह लेना आसान नहीं होगा लेकिन आज कपड़ा उद्योग परिधान तक सीमित नहीं है.

21,000 लगाओ-55,000 पाओ!

निवेश का बड़ा धोखा, मंत्री के नाम पर लूट की कोशिश

नई दिल्ली, 16 नवबंर. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से फैल रहा है, जो लोगों को आसानी से ठगी का शिकार बना सकता है. यह वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बताकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा है कि एक निवेश प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 21,000 लगाने से एक ही दिन में 55,000 का मुनाफा मिलेगा.

वीडियो इतना असली दिखता है कि पहली नजर में कोई भी इसे

सच मान ले. लेकिन सरकार की प्रेस एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ कर दिया है कि यह वीडियो पूरी तरह डिजिटल रूप से बदला हुआ है और इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं. वित्त मंत्री ने ऐसी किसी योजना का न प्रचार किया है और न मंजूरी. लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे 'जल्दी अमीर' बनाने वाले दावों से सावधान रहें.

सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सामग्री का फैलना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब ऐसे वीडियो किसी शीर्ष सरकारी मंत्री से जुड़े हुए हों, तो खतरा और बढ़ जाता है. हाल ही में फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार कर रही हैं.

सोने के भाव रहे स्थिर

नई दिल्ली, 16 नवबंर. देश में सोने और चांदी के दाम कल रविवार, 16 नवंबर को बिल्कुल शांत दिखाई दिए. शनिवार को आई तेज गिरावट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कल के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन घरेलू सर्राफा बाज़ार ने निवेशकों को राहत दी. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त टिप्पणी और कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव देखा गया था, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा और सोना-चांदी दोनों बुरी तरह टूटे. हालांकि, सप्ताहांत पर ट्रेडिंग बंद होने की वजह से आज रेट स्थिर रहे.

आरबीआई के नये उपायों का निर्यातकों ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 16 नवंबर. निर्यात संघों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने वैश्विक बाजार के बदलावों से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों पर कर्ज और उधार के भुगतान का दबाव कम करने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कदमों को बड़ी राहत बताते हुए इसका स्वागत किया है.

केंद्रीय बैंक ने निर्यात आय देश में लाने के लिए तय अधिकतम समय को नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने कर दिया है. इसके साथ ही उसने निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर माल को भेजने की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है.

फियो के एक बयान में कहा गया है कि इससे इस समय वैश्वक बाजार की कठिनाइयों से प्रभावित क्षेत्रों के निर्यातकों पर ऋण चुकाने का दबाव हल्का होगा और वे रोजमर्रा के काम काज की ऋण सुविधाओं से धन निकासी को नये ढंग से पुनर्व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा.

समाचार विशेष

बिहार चुनाव में पीके के प्रदर्शन से उठे सवाल

नई दिल्ली. राजनीति में प्रशांत किशोर की छवि कुछ वक्त पहले बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार के रूप में देखी जाती थी. पीके को कई राजनीतिक दलों और नेताओं की चुनावी सफलताओं का स्क्रिप्ट राइटर माना जाता है लेकिन उनका सबसे बड़ा दांव बिहार में बुरी विफल साबित हुआ है. चुनावी नतीजों ने जनसुराज के एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिली.

तीन साल पहले जब चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले प्रशांत किशोर ने बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं से राज्य को मुक्ति दिलाने का वादा किया था. तो वह अपनी बोलने की बेहतरीन कला, सत्ता पक्ष पर हमला और वादों के कारण सुर्खियों में आए. साथ ही उन्होंने पूरे चुनाव अभियान के दौरान जनता से वादा किया कि वह बिहार से पलायन रोकने की दिशा में काम करेंगे.

बिहार में क्यों चर्चा में थे?- प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में और इजाफा इस बात से हुआ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया था, साथ ही कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों के लिए चुनावी कैंपेन कर उन्हें जीत दिलाई. हालांकि 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों प्रशांत किशोर ने कैंपेन किया था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा. उनकी असफलता के बावजूद उनकी छवि बनी रही. वे अक्सर पर्दे के पीछे रहने वाले रणनीतिकारों से अलग, खुलकर अपनी राय रखते थे और उन नेताओं की आलोचना करते थे जो उनके प्रति उदार नहीं थे, जैसे कि राहुल गांधी.

गलत साबित हुआ पीके का दावा

प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनकी पार्टी जदयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी. लेकिन, एनडीए की सुनामी के बीच जदयू ने 85 सीटें जीतीं और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं. किशोर ने यह भी कहा था कि अगर उनकी भविष्यवाणी गलत हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे, जो अब उन पर भारी पड़ सकता है. फिलहाल बिहार चुनाव के नतीजों के साथ ही पीके की एक राजनीतिक रणनीतिकार के तौर चमक फीकी पड़ गई है. हालांकि, राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार ने प्रशांत किशोर की उस अपरंपरागत राजनीति के लिए एक छोटी सी राह खोली है, जिसने अब तक जातिगत समीकरणों को दरकिनार कर शिक्षा और रोजगार जैसे सार्वभौमिक सार्वजनिक हित के मुद्दों को प्राथमिकता दी है.

नए चेहरों की मांग-पुराने से मोहभंग

बदलाव और विकास की उम्मीद में भंडारा के शहरवासी

मुंबई. भंडारा में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में इस बार अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. अब तक राजनीतिक दलों द्वारा बार-बार एक ही पुराने चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने की परंपरा पर नागरिक सवाल उठा रहे हैं.

शहर में यह चर्चा तेज है कि यदि युवा, सक्षम और नए चेहरों को मौका दिया जाए, तो शहर के विकास की दिशा पूरी तरह बदल सकती है. स्थानीय नागरिकों और जानकारों का कहना है कि वर्षों से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल एक जैसे उम्मीदवारों को उतारते रहे हैं. कई नेताओं ने दल बदलकर अपनी सक्रियता बनाए रखी है, लेकिन इसके बावजूद शहर की बुनियादी समस्याओं पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है. सड़कों की बदहाली, बढ़ता अतिक्रमण, कचरे के ढेर और यातायात अव्यवस्था जैसी समस्याएँ पहले से अधिक गंभीर होती जा रही हैं. अब तक चुने गए जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता का खामियाजा शहरवासी लगातार भुगत रहे हैं.

शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. सड़कें संकरी होती जा रही हैं और यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है. नागरिक ऐसे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो साहसिक निर्णय लेकर अतिक्रमण हटाए और शहर को व्यवस्थित करे. कूड़े के ढेर बदबू व स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रहे हैं, जबकि आवारा कुत्ते और पशुओं की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है. नगर परिषद की बकाया वसूली में असफलता के कारण विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि का भी अभाव बना हुआ है.

नए नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रहे नागरिक

नागरिकों का मानना है कि शहर की नीरस और अव्यवस्थित सूरत बदलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है. युवाओं, नए चेहरों और कुशल नेतृत्व को आगे लाने से ही शहर में सकारात्मक बदलाव संभव है. लोगों का कहना है कि पुराने चेहरों ने वर्षों तक शहर की समस्याओं की अनदेखी की है, इसलिए इस बार चुनाव में बदलाव आवश्यक है.

बंगाल में बूथों पर भाजपा के पास लोग नहीं

कोलकाता. चुनाव आयोग ने जब से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया और 12 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है तब से पश्चिम बंगाल में विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है.

एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि 75 फीसदी मतदाताओं के पास मतगणना प्रपत्र पहुंच गया है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी इसके विरोध में या इससे लड़ने में लगी है. ताजा विवाद बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति को लेकर छिड़ा है. चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए की नियुक्ति की शर्तों में थोड़ी ढील दी है. अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि ऐसा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है.

गौरतलब है कि अभी तक बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए यह शर्त थी कि पार्टियां, जिसे बीएलए बनाएंगी वह उसका नाम वहां की मतदाता सूची में होना

विशेष | शिवकुमार यादव की वापसी से मचा हड़कंप, होगी कांटे की टक्कर

नागपुर. नगर परिषद व नगर पंचायत चुनाव की रणभेरी बज गई है. चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो गए हैं और उम्मीदवारों के चयन के प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों में चल रही है. इसके साथ ही दूसरे चरण में जिला परिषद के होने वाले चुनाव के लिए भी पार्टियों ने अपनी गोटी बिठाना शुरू कर दिया है. जिले में हमेशा भाजपा व कांग्रेस ही मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही हैं.

बीते चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात देकर जेडपी में अपना कब्जा जमा लिया था. उसके बाद जिले में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी व सहयोगी दलों ने तोड़फोड़ की राजनीति शुरू की.

नागपुर जिले में चुनावी महाभारत!

ग्रामीण भागों के अनेक दिग्गज पदाधिकारियों को भाजपायी बनाया गया. एकमात्र उद्देश्य जिले में भी अपना वर्चस्व बनाना है. जिला परिषद में वापसी के लिए साम-दाम-दंड-भेद की नीति के साथ बीजेपी अपनी रणनीति में जुटी हुई है लेकिन कांग्रेस भी हार नहीं मान रही है. वह भी किसी कीमत पर जेडपी की सत्ता गंवाना नहीं चाहती लेकिन यह भी सच है कि सत्ताधारियों के सामने उसकी इस बार की चुनौती कठिन होगी.

टेकाड़ी में यादव बनाम यादव- दोनों ही पार्टियां जीत की गारंटी वाले उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने की जुगत में हैं. पूर्व जिप अध्यक्ष रश्मि बर्वे 2019 के चुनाव में टेकाडी सर्कल से चुनकर आई थीं. वहीं समीप के साटक सर्कल से बीजेपी के वेंकट कारेमोरे जीते थे. इसके पूर्व के 2012 के चुनाव में कांग्रेस के शिवकुमार यादव इस सीट से जिप सदस्य चुने गए थे. अब नये परिसीमन में टेकाड़ी सर्कल का कांद्री नगर पंचायत हो गया है. पारशिवनी भी नगर पंचायत है.

कन्हान नगर परिषद बन गया जिससे ये सर्कल से अलग हो गए हैं. बीजेपी के कारेमोरे का गांव नीलज सहित साटक में आने वाले 10 गांव अब टेकाड़ी सर्कल में जुड़ गए हैं. इससे भाजपा की ओर से वे टिकट के लिए दावा ठोकेंगे, लेकिन चर्चा है कि कांग्रेस की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके और अब भाजपायी हुए गज्जू यादव भी बीजेपी की टिकट से इस सर्कल में उतरने की तैयारी में हैं.

कहीं टकराएंगे दिग्गज, कोई बदलेगा सर्कल

नये सर्कल रिधोरा में भी दो दिग्गज टकरा सकते हैं. इस सीट से सलिल देशमुख और पूर्व जिप उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चिखले की करारी टक्कर देखने को मिल सकती है. बता दें कि मेटपांजरा सर्कल के चंद्रशेखर चिखले संयुक्त राष्ट्रवादी पार्टी की टिकट से चुनाव जीते थे और जिप उपाध्यक्ष भी रहे. 2019 के चुनाव में लेकिन चिखले का पत्ता पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलिल देशमुख के लिए काटा गया. तभी से वे नाराज चल रहे थे. जब विधानसभा चुनाव में भी सलिल को उम्मीदवारी दी गई तब अनेक कार्यकर्ताओं ने इसे पुत्र मोह बताया और नाराज चिखले ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए.